शेयरों के मूल्यों में गिरावट

239. **श्री सोमपाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में रुपये के मूल्यों में गिरावट के कारण शेयरों के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की दृष्टि में देश की औद्योगिक और आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है; और

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिये कोई कदम उठाये हैं/या उठाने जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल): (क) स्टाक बाजार में शेयरों की कीमतों में विभिन्न कारकों की अन्तः क्रिया के कारण उतार-चढ़ाव हो सकता है जैसेः समग्र आर्थिक माहौल और नीति के संबंध में निवेशकों की प्रत्याशाएं, कार्पोरेट क्षेत्र का कार्य-निष्पादन, विशाल संस्थागत निवेशकों द्वारा किये गये लेन-देन, स्टाक बाजार में व्याप्त विचार और विदेशों में पूंजी बाजार की प्रवृत्तियां। इसलिए शेयरों की कीमतों में हुई हाल की गिरावट की कोई एक वजह नहीं कही जा सकती।

(ख) और (ग) चूंकि शेयरों की कीमतों में हुई हाल की गिरावट को अस्थायी घटना कहा जा सकता है जो कि मुख्यतया स्टाक बाजार में तकनीकी कारकों का परिणाम थी, इसलिए इसका अर्थव्यवस्था और औद्योगिक उत्पादन पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। सरकार या सेबी शेयर की कीमतों की घटबढ़ को प्रभावित करने के लिए स्टाक बाजार में दखल नहीं देते।

विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख उत्सर्जन मानदण्डों का उल्लंघन किया जाना

240. **श्री सोमपाल:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा वातावरण में भारी मात्रा में राख का उत्सर्जन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश ताप विद्युत संयंत्र निर्धारित मानदंडों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे ताप विद्युत संयंत्र कौन-कौन से हैं और सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन ताप विद्युत संयंत्रों को इसकी निश्चित तारीख तक अपनी व्यवस्था को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): (क) जी, हां।

(ख) से (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपनी दिनांक 12.2.1992 की अधिसूचना के द्वारा निर्धारित किया है कि 16.5.81 के बाद चालू की गई ताप विद्युत उत्पादक यूनिटों को 31.12.92 तक उत्सर्जन के लिए निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन करना होगा, जबकि पहले प्रचालन शुरू करने वाली यूनिटों को 31.12.93 तक इन मानदण्डों का अनुपालन करने की अनुमति होगी।

31.8.95 की स्थिति के अनुसार इन मानदण्डों का अनुपालन किए जाने की स्थिति, जैसा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है, इस प्रकार है कुल 97 विद्युत यूनिटों में से दो को बन्द कर दिया गया था, 62 यूनिटों में मानदण्डों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त सुविधा विद्यमान है, 28 यूनिटों को 1981 से पहले चालू कर दिया गया था और 1981—91 के बीच चालू की गई पांच यूनिटों में पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं। की गई कार्रवाई/की जा रही कार्रवाई की संयंत्रवार विस्तृत स्थिति अनुपत्र में दी गई है [देखिए परिशिष्ट 175, अनुपत्र सं० 4]

Shortage of Power

241. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the shortage of power in general and during peak period at present;

(b) whether resource constraints, increased economic activity and power distribution and transmission losses are main reasons for the worsening power situation; and

(c) if so, the steps taken to increse plant load factor and to reduce T&D losses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) During the period April-October 1995, the country faced 8%-9% energy deficit and 15%-16% peaking deficit.

(b) The main reason for power shortage in the country is the gap between the demand and supply of power coupled with constraints of funds for undertaking the required capacity addition programme, renovation of power plants and system improvement schemes. High transmission and distribution losses and sub-optimal utilisation of existing assets have also contributed to low availability of power.

(c) Various measures have been taken by Government for optimum utilisation of installed capacity such as renovation and modernisation of old units, monitoring supply of requisite quantity and quality of coal, training of operation and maintenance personnel and strengthening of transmission and distribution system, etc. To enable power utilities to take measure in a planned way, comprehensive guidelines have been issued to power utilities for reducing transmission and distribution losses. These include, conducting of energy audit for identifying the system elements responsible for excessive losses, installing capacitors to improve the voltage profile, preparation of system improvement schemes for strengthening and improving their transmission and distribution systems, installing temper-proof meter boxes to check theft of energy and setting up vigilance squads to detect cases of theft of energy. Theft of energy has been made a cognizable offence from August, 1986 under the provision of Section 39 of Indian electricity Act, 1910. To motivate the State Electricity Boards and their employees to reduce transmission and distribution losses and to increase the energy generation in thermal power stations, separate incentive schemes in the form of cash awards/shields are in operation.

Cost and time over run in Power projects

242. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the average cost over run per project and time over run per project in the power sector during the Sixth, Seventh and Eighth Five Year Plan;

(b) the reasons for higher cost over run and time over run per project; and

(c) the measures taken by Government to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) to (c) The Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Awarding of Power Project Contract to Reliance Group Companies

243. SHRI GOVIND RAM MIRI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Reliance group of companies has recently been awarded a contract for the prospecting of power projects in Patel Ganga and Raigarh district of Maharashtra;

(b) if so the terms and conditions thereof; and

(c) whether any malpractice has been involved in awarding of the contract?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) and (b) The Maharashtra State Electricity Board (MSEB) have informed that Government of Maharashtra have approved the propoosal of M/s. Reliance, under competitive bidding process, for setting up a power project in Patel Ganga, Raigarh district of Maharashtra and that the power Purchase Agreement, which sets out detailed terms and conditions, is yet to be finalised.